16.03 hours

Title: Discussion regarding recent summit-level talks held between India and Pakistan in Agra. (Not concluded)

MR. SPEAKER: Now, we shall take up item no. 27 − Discussion under Rule 193.

Time allotted is two hours.

Hon. Members, I have to inform the House that Shri Ramji Lal Suman, in whose name the Discussion under Rule 193 on the statement made by the Prime Minister regarding `recent Summit-level talks held between India and Pakistan in Agra' is listed, has requested me to allow Shri Mulayam Singh Yadav to initiate the discussion on his behalf. I have allowed Shri Mulayam Singh Yadav to raise the discussion.

Hon. Members, I need not emphasise the importance of the issues involved and the implications for peace in the region. The whole nation is keenly interested in the issue. Let the discussion be marked by reason, restraint and responsibility. This applies to all sections of the House. Let this august House send the right message.

Now, Shri Mulayam Singh Yadav.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है, मैं आपसे सहमत हूं कि आज की बहस गंभीर विाय पर है। यह गंभीर विाय है और गंभीर विाय पर गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वे तथ्य तो जानकारी में थे लेकिन कुछ आंतरिक तथ्य भी थे, उन तथ्यों को पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ जी ने पाकिस्तान में जाकर और कुछ आगरा में बैठकर उजागर किये लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी को ही पहले बातें बता देनी चाहिए थी क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने आरोप लगा दिया कि यह बातचीत भारत की वजह से विफल हुई। क्या अंतराट्रीय स्तर पर भारत की छवि इससे धूमिल नहीं हुई । इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं, ये बातें आपके वक्तव्य के माध्यम से देश के सामने, जनता के सामने आनी चाहिए थी कि यह मुशर्रफ साहब का वक्तव्य गलत है या सही है। प्रधानमंत्रीजी स्पट कीजिये।

जहां तक बातचीत का सवाल है, यह हम पहले ही बताना चाहते हैं कि हमारा दल, समाजवादी पार्टी और समाजवादी आन्दोलन, इस बात का पक्षधर रहा है और आज भी है कि पाकिस्तान के साथ सभी विवादों को बातचीत के साथ हल किया जाए। यह इसलिये भी जरूरी है कि भारत एक बडा और मजबूत पडौसी है और दोंनों की संस्क्रति एवं विरासत भी एक है। एक अवसर ऐसा आएगा कि यह बातचीत कामयाब हो सकती है। ऐसे हम आशावादी हैं। बातचीत का सिलसिला आपने चलाया । स र्वदलीय बैठक में हम सबने आपका समर्थन किया और आज भी हम यह कहना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में आपकी बातचीत हो, तो उस बातचीत के हम समर्थक हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी इसलिए बरतनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अलग होने के बाद 54 साल में लगातार बातचीत और साथ-साथ युद्ध लडने का इतिहास रहा है। बातचीत हमेशा भारत ने की और युद्ध हमेशा पाकिस्तान ने थोपा है। युद्ध में हमेशा पाकिस्तान हारा है और हिन्दुस्तान जीता है । जब-जब युद्ध के बाद बातचीत हुई है, तो बातचीत में पाकिस्तान जीता है और हिन्दुस्तान हारा है। यह हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी बातचीत हुई है, बातचीत में हिन्दुस्तान हारा है और युद्ध में हिन्दुस्तान जीता है और बातचीत में पाकिस्तान जीता है। लगभग यही स्थिति और परिणाम आगरा में भी हुआ।

महोदय, शुरु-शुरु में आपने देश के सामने मजबूती से एक कदम उठाया था। आपने पत्र 23 मई को लिखा । आपने यह पत्र किन परिस्थितियों में लिखा, जबकि एक हफ्ते पहले आप कह चुके थे कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं रोकेगा, आतंकवाद सीमा पार से बन्द नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी और जब तक लोकतान्त्रिक सरकार पाकिस्तान में नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल ही नहीं है । इसी बीच, चाहे कमीशन कहिए या कमेटी या एक व्यक्ति आपकी तरफ से, श्री के सी पंत जी, उनको काश्मीर की समस्या के समाधान के लिए आपने नियुक्त कर दिया। वे वहां बुद्धिजीवियों या जो भी दल है या जो उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले हैं या समर्थन करने वाले हैं, जो भी वहां घटक हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ-साथ वहां जितने भी विरोधी दल है, उन सभी दलों से बातचीत कर रहे थे । वे बैठे हैं, श्रीनगर में या लद्दाख में या जम्मू में और पंतजी की रिपोर्ट भी नहीं आई। तब तक आपने जनरल मुशर्रफ को निमंत्रण दे दिया। इसलिए यह स्पट होना चाहिए कि प्रधानमंत्रीजी की कौन सी परिस्थितियां आ गई थीं, क्या मजबूरी थी जिनकी वजह से जल्दी से जल्दी आपने उन्हें भारत आने हेतू निमंत्रण भेजा। मुशर्रफ साहब ने स्पट किया है, पत्र लिखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अमेरिका के दबाव में । अगर पत्र विदेशी के दबाव में लिखा है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्यों ऐतराज नहीं है? क्योंकि मैं मानता हूं कि 1947 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान, हम दोनों भाइयों को लड़ा दिया था और हम अलग-अलग हो गए थे। एक विदेशी ने अलग-अलग कर दिया । अगर कोई विदेशी लुक-छुप कर हम दोनों की दोस्ती करा देता है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन काश्मीर के मामले में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं है। यदि है, कोई विदेशी दोस्ती करा देता है, तो हमें ऐतराज नहीं है। करा देता है, तो बहुत अच्छा है।

जहां तक दोस्ती का सवाल है, यह दोस्ती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना दोस्ती किए, दोनों देशों की जनता खुशहाल नहीं हो सकती है। धीरे-धीरे जनता इस बात को महसूस करने लगी है। यह अलग बात है कि हम जनता को जगा कर दोस्ती हेतु तैयार नहीं कर पाये हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी ।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान की दोस्ती इसलिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान उसका एक मजबूत पड़ोसी है और दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत एक ही है। हमने बातचीत के दौरान देखा जनरल मुर्शरफ एवं अन्य पाकिस्तानी प्रतिनिधि पाकिस्तानी भााा में बातचीत कर रहे थे और हमारे लोग उनसे विदेशी भााा अंग्रेजी में बात कर रहे थे। यह मैंने भोज के दौरान भी देखा और दूसरी जगह भी देखा। यह अच्छी बात नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है कि वे अपनी भााा में बात करते हैं। प्रधान मंत्री जी, आप तो विदेश मंत्री की हैसियत से, कमेटियों के माध्यम से और गांधी जी की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी पूरी दुनिया में बहुत घूमे हैं। भााा के संबंध में, आप हिंदी भााा के प्रयोग का पालन भी करते हैं लेकिन सिर्फ 95 फीसदी करते हैं, भााा के सवाल को लेकर आप भी 5 फीसदी गड़बड़ा जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि प्रधान मंत्री जी एवं भारत के अन्य प्रतिनिधि अंग्रेजी भााा में बोल रहे थे। दोनों राट्रों की सांस्कृतिक विरासत एक है, इसलिये दोनों देशों की जनता की भावनाओं को रोका नहीं जा सकता। दोनों देशों की जनता परस्पर दोस्ती चाहती है और जहां तक दोस्ती एवं एका की बात है, हम और समाजवादी पाटी इसके पक्ष में हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए इस बात को पहले से ही कह दिया, क्योंकि आपका निर्देश हो गया था। हम सब को अहसास था कि वार्ता की सफलता संभव नहीं है परंतु सभी ने वार्ता का समर्थन इसलिये किया था क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध के क्या परिणाम होते हैं। लेकिन सावधान करने की जरूरत इसलिए है कि जब-जब बातचीत होती है तो युद्ध हो जाता है। आप जब लाहौर बस लेकर गए तो करगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा करने का प्रयास किया जिसकी परिणति युद्ध के रूप में हुई।

पाकिस्तान के राट्रपति ने कहा कि कश्मीर की समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक युद्ध की संभावना रहेगी। पाकिस्तान पहुंचकर जनरल मुशर्रफ ने अपनी प्रेस वार्ता में जो कुछ कहा वह सरासर अपमानजनक है। शिमला समझौता और लाहौर घोाणापत्र जिनमें भारत का एक पक्ष है, का अपमान, भारत की प्रभुसत्ता का अपमान है। हमने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी तब तक युद्ध की संभावना है और युद्ध भयंकर हो सकता है।

महोदय, जहां तक कश्मीर का सवाल है, हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि आप इस्लामाबाद जरूर बातचीत करने जाएं, लेकिन हिन्दुस्तानी नागरिकों के स्वाभिमान और भारत की प्रभुसत्ता की कीमत पर कोई वार्ता नहीं होनी चाहिये। देश की जनता के मन में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि भारत सरकार ने बातचीत के लिये पूरी तैयारी क्यों नहीं की। जब जनरल मुशर्रफ ने कश्मीर का एजेंडा बातचीत का एकमात्र मुद्दा घोाित किया तब हम क्यों यह दोहरा रहे थे कि बातचीत का कोई मुद्दा नहीं है। हिन्दुस्तान का मीडिया भी इस वार्ता में भारतीय पक्ष को ठीक तरीके से अंतर्राट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा पाया। इस कूटनीति में आप असफल हुए हैं। इसकी क्या वजह थी, यह आप बताएं। मैंने शुरु में कहा कि जब-जब बातचीत होती है तो पाकिस्तान जीत जाता है, हिन्दुस्तान हार जाता है और जब-जब युद्ध होता है तो हिन्दुस्तान जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है। यह बात दिमाग में रहनी चाहिए कि जो लोग बातचीत में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हों- चाहे विदेश मंत्री हों, या अन्य प्रतिनिधि हों, बिना किसी एजेंडें और अधकचरी तैयारी के साथ वार्ता नहीं होनी चाहिये। 23 मई को प्रधानमंत्री जी ने बातचीत के लिये निमंत्रण भेजा और 24 मई को पाकिस्तान के राट्रपति जी को वह पत्र मिल गया, 25 मई को उन्होंने फैसला कर लिया कि हम हिन्दुस्तान आएंगे। 25 मई से 13 जुलाई तक पाकिस्तानी राट्रपति ने बार-बार अपना बयान बदला और हर बार दोहराया कि वे कश्मीर के मुद्दे पर ही बातचीत करेंगें। आप 28 जून का अखबार पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि वह मैं पाकिस्तान के पहले शासक हैं जिन्हें केवल कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिये बुलाया गया है। यह एक गलत और झूठा बयान था।

भारत की ओर से गोलमाल सफाई दी जा रही थी। प्रधानमंत्रीजी ने दो-टूक शब्दों में यह नहीं कहा कि कश्मीर को बातचीत का केन्द्र-बिंदु नहीं बनाया जायेगा। यह दो-टूक जवाब आपको देना चाहिए था। क्या परिस्थितियां रहीं, क्यों ऐसा नहीं हुआ, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। प्रधानमंत्रीजी को स्पट शब्दों में कहना चाहिये था कि कश्मीर के संबंध में वार्ता केवल आतंकवादियों की ओर से किये जा रहे हमले को लेकर होगी।

बातचीत में आप हारते हैं और लड़ाई के मोर्चे पर आप जीतते हैं। हमने रणनीति की दृटि से अत्याधिक महत्पूर्ण जीते हुए क्षेत्र पाकिस्तान को वापिस कर दिये। एक लाख से अधिक पाकिस्तानी बंदी सैनिक वापिस कर दिये किन्तु 100 भारतीय युद्धबंदियों को वापस नहीं करा सके। यह अलग बात है कि आप उन जवानों को युद्धबंदी कहें और पाकिस्तान मानता हो कि ये जासूसी करने वाले लोग थे। इसी नाम से अगर बंदी बना रखे हों, तो भी कानून के तहत हमारे जिन जवानों को गिरफ्तार किया है उन्हें छोडना चाहिये। परन्तु आप उन जवानों को नहीं छुड़वा सके तो इससे ज्यादा और क्या आपकी असफलता हो सकती है।

मेरा कहना यह है कि भारतीय युद्धबंदी 100 जवानों को छुडवाने का कार्य सबसे बातचीत में आपको करना चाहिए। बातचीत हो तो आपको कहना चाहिए कि चाहे जासूसी के नाम पर ही गिरफ्तार किए गये हों उन्हें तुरन्त छोडना चाहिये। पाकिस्तान बार-बार कह चुका है कि भारत का कोई भी युद्धबंदी पाकिस्तान में नहीं है तो कैसे अब वह मान ले कि कोई युद्धबंदी उनके यहां है। आपको उनको कहना चाहिए कि यह कोई मान-अपमान की बात नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप एक बार मना कर चुके हो कि नहीं है तो नहीं है। इसलिए बातचीत में यह आना चाहिए कि हमारे जो 100 जवान युद्ध बंदी हैं जिनका प्रमाण हमने उन्हें दिया है उन्हें किसी भी तरह से हमें छुड़ाना चाहिए।

उनके परिवार वाले तो उन्हें भुला चुके थे लेकिन जब से बातचीत का सिलसिला शुरु हुआ तो वे बहुत भावुक हो गये कि अब उनके लोग छूट जाएंगे। उनके बच्चे, पत्नी और सगे-संबंधी मुझसे भी मिले हैं और आपसे भी मिले होंगे और बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद जगी कि उनके लोग अब छूटकर आ जाएंगे। आगरा में पाकिस्तान के राट्रपति ने कह दिया कि हम व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देखेंगे। जाने के बाद यह भी कह दिया कि हमारे यहां कोई युद्धबंदी नहीं है। बातचीत के माध्यम से जो भावनाएं संगे-संबंधियों के मन में जागी थीं कि उनके रिश्तेदार मिल जाएंगे, उन पर पूरी तरह से पानी फेरा जा चुका है।

इसलिए हमने कहा कि जब-जब बातचीत होती है तो हम लोग हार जाते हैं, लेकिन युद्ध होता है तो जीत जाते हैं। यह मैंने एक उदाहरण दिया है, भारतीय जमीन के बारे में दिया है, अब हम उसका उदाहरण नहीं देंगे, चूंकि बातचीत हो रही है, वरना हम जानते हैं कि जो इलाका दिया है, उसे कैसे और किन परिस्थितियों में दिया गया है, वे ऐसी बातें हो गई हैं, जिन्हें हम कहना नहीं चाहते। लेकिन देश के सवाल पर इतिहास को कभी झुठलाया नहीं जा सकता, इतिहास को दबाया नहीं जाना चाहिए। यदि भूलों को सामने रखकर हम बातचीत करेंगे तो आगे हमसे कोई बड़ी भूल नहीं होगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं और इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि किसकी सरकार थी, किसके साथ समझौता हुआ था, लेकिन सच्चाई, सच्चाई है। जब जनरल मुशर्रफ बार-बार कश्मीर की बात करते थे तो भारत ने पाक अधिक्रृत कश्मीर को वापस लेने की बात क्यों नहीं की । क्या अंतर्राट्रीय स्तर पर इस बात का प्रचार-प्रसार आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान भारत के एक हिस्से पर जबरन कब्जा किये बैठा है और उसे वह खाली करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, आप अमरनाथ यात्रा को ही ले लीजिए। अमरनाथ यात्रा में जो कुछ आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है, उससे उन्होंने पूरे कश्मीर की सभ्यता और संस्कृति को तहस-नहस किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। लेकिन प्रधान मंत्री जी केवल निन्दा से काम नहीं चलेगा। आतंकवादियों को रोकने में आपकी सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। उसका सबसे बडा उदाहरण यह है कि जब तक आपका लाल किला सुरक्षित नहीं है तो हिंदुस्तान का एक भी आदमी यह नहीं कह सकता कि हम सुरक्षित हैं। इसलिए आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, उसे रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उसी का परिणाम है कि एक साल बाद अमरनाथ यात्रा में इतने लोगों को मारने की हिम्मत की गई, जबकि पिछले साल पूरी सावधानी बरती गई थी, मीटिंगे की गईं, हम सारे विपक्ष के नेता पहलगाम में मौके पर गये थे, और उसके बाद अमरनाथ यात्रा हुई। लेकिन इस बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी सदन को निन्दा करनी चाहिए। किसी भी तरफ से अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। जिन परिस्थितियों में यात्रा हो रही है, जो लोग वहां से लौटकर आये हैं, आप उनसे पूछिये। वे कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा क्या, हम किसी तरह से बचकर आये हैं। ऐसी भावना पैदा हो गई है। इसका सीधा-सादा मतलब यह है कि आतंकवाद को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पता नहीं कैसे रणनीति बनाई जाती है। जब-जब भी आपने युद्धविराम किया, हमारे लोगों की ज्यादा जाने गईं। आंकड़े कितने भी दिये जाएं, लेकिन जब-जब युद्धविराम हुआ है, ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। जाने किन परिस्थितियों में युद्धविराम होता है, फिर लागू होता है और फिर युद्धविराम किया जाता है - पता नहीं इस सरकार का क्या स्टैन्ड है, आप क्या चाहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यह सरकार देश के संवेदनशील मामलों में, आतंकवादियों के मामलों में, सीमा की सुरक्षा में और कारगिल के सवाल को लेकर भ्रमित है। देश की सुरक्षा कैसे की जायेगी, कैसे आतंकवादियों का मुकाबला किया जायेगा, कुछ पता नहीं है। प्रधान मंत्री जी जब-जब युद्ध होते हैं तो नई-नई सीमाएं बनती हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, लेकिन यह दुर्भाग्य हमारे देश का है कि युद्ध के बाद हमारे देश की सीमा ज्यों की त्यों रहती है या कम हो जाती है। युद्ध भी हो जाता है और कुछ चला भी जाता है। दुनिया में जब-जब युद्ध हुए हैं तो हमेशा नई सीमाएं तय हुई हैं। लेकिन यही हिंदुस्तान है जिसमें युद्ध के बाद सीमाएं सिकुड़ती हैं। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमने दुनिया में देखा है कि जब-जब युद्ध हुए हैं, नई सीमाएं बनी हैं, आज आप हमें बतायेंगे, चर्चा यह भी है कि पूरा कारगिल ज्यों का त्यों हमारे हाथों में नहीं आ पाया है। अब यह सच है या गलत, इस बारे में आप जानते होंगे या रक्षा मंत्री जी जानते होंगे। जब आप जवाब दें तो हमें और देश को संतुट करिये कि कारगिल में हमारी जितनी जमीन थी, उस पर हमने ज्यों का त्यों कब्जा कर लिया है और उस कब्जे में हमारे शहीदों को कितना अपमानित होना पड़ा है। अब तो क्लिंटन साहब ने भी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की सैनायें हमने हर्टवाईं।

इस सभागार में आप सभी आसन पर बैठे हुए थे और सारी दुनिया देख रही थी। उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं हमने हटाईं। हमारे शहीदों की कुर्बानी बेकार गई। इस तरह से हमारे देश के सम्मान पर जो चोट आती है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश की सैन्य शक्ति बहुत विशाल है और हमारे जवान बहुत बहादुर हैं। जिन परिस्थितियों में हमारे जवान लड़ते हैं, उसके बाद भी दूसरे देश का राट्रपति आकर हमारी संसद में आकर यह कह

कर चला जाए कि पाकिस्तान की फौजें मैंने हटवाई थीं तो यह शर्मनाक बात है और आपने विजय का डंका बजाकर चुनाव जीत लिया। सच बात सामने आनी चाहिए कि क्लिंटन सच हैं या आप सच हैं। इस मौके पर आपको साफ-साफ बताना होगा। मैंने इसी सदन में सवाल किया था तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इसका हम क्या जवाब दें। इसका जवाब रक्षा मंत्री दें चाहे प्रधान मंत्री दें मगर इसको साफ करना चाहिए कि हमारी फौज के जवानों ने, अधिकारियों ने पाकिस्तान की फौजें हटाई हैं या विदेशियों ने हटाई हैं, यह साफ हो जाना चाहिए। अब तो किताब लिख दी गई है। हमारे जवानों ने लड़ाई में जो कुर्बानी दी, उस पर कलंक लग रहा है। इसलिए हमने आपसे कहा और आपसे चाहा कि साफ उत्तर दें।

जहां तक बातचीत के परिणाम का सवाल है हम सभी चाहते हैं कि वे अच्छे निकले। हम यह चाहते हैं कि यह सिलसिला बना रहे, बातचीत होती रहे लेकिन यह कैसे होगा कि बातचीत भी हो रही है और लोग सीमा पर मारे जा रहे हैं, किसान अपने खेत काट नहीं पा रहा है, बो नहीं पा रहा है। आगरा में बातचीत हो रही है और सीमा पर तोपों की आवाजें आ रही हैं, बंदूकों की आवाजें आ रही हैं और उसके बाद पाकिस्तान के राट्रपति प्रेस कॉनफ्रेन्स में कहते हैं कि जिस तरह से मुक्तिवाहिनी सेना थी 1971 में, उसी तरह से यह भी कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने जेहादी हमलों का समर्थन करते हुए आतंकवादियों को जंगे-आजादी का मसीहा बताया है। इस प्रकार इस बातचीत के माध्यम से एक अफसोस की बात यह हुई । जब जनरल मुशर्रफ आपकी जमीन पर, आगरा में बैठकर यह कहकर चले गए तो सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की बातचीत वे करने जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हम बात करेंगे तो आपने कहा कि कश्मीर का कोई बड़ा विवाद नहीं। अगर आपने यह मान लिया है तो आपने मान लिया है कि पाकिस्तान कश्मीर का लगभग 40 फीसदी जो हिस्सा दबाए बैठा है, वह पाकिस्तान का नहीं है? यह बात साफ होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने कहा है और साफ-साफ कहा है और उन्होंने कहा कि कश्मीर पर विवाद है , और आपने कहा कि विवाद नहीं है तो इसके मायने यह कि विवाद नहीं है और सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर पर विवाद है और कश्मीर का एक तिहाई या 40 फीसदी हिस्सा पाकिस्तान अवैध रूप से अधिग्रहीत किए हुए है। क्या आपने यह सवाल उठाया कि 40 फीसदी हिस्सा वह वापस दें? क्या अंतर्राट्रीय स्तर पर आपने प्रचार किया कि पाकिस्तान हमारे कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा दबाए बैठे है? क्या इसमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, क्या दुनिया को नहीं बताना है कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान दबाए बैठा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? आपको बताना चाहिए । वे कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद कराएंगे तो क्या आपने कहा कि कश्मीर का जो 40 फीसदी हिस्सा दबाए बैठे हैं, वह आपको हमें देना पड़ेगा? हम फिर कहना चाहते हैं कि आपको अंर्तराट्रीय स्तर पर प्रचार करना पड़ेगा कि अवैध रूप से पाकिस्तान 40 फीसदी कश्मीर का हिस्सा दबाए बैठा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पूरा सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि पाकिस्तान जब कश्मीर की बात करता है, तो हमें भी उसके कब्जे में अपने कश्मीर का जो 40 प्रतिशत हिस्सा है, उसकी बात करनी चाहिए। â€¦(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुजा) : प्रधान मंत्री जी, मजबूती के साथ, खूंटा गाढ़ आए हैं। इसलिए हम यहां शांति के साथ बैठे हैं। ... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने खम्भा गाढ़ दिया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, दो-तीन बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वोट का लालच रहेगा तब तक दोस्ती नहीं हो सकती है। हमें वोट का कोई लालच नहीं है। जब चुनाव हुए थे, तो हमें वोट का कोई लालच नहीं था, लेकिन आप तो थर-थर कांप रहे थे। यदि मैं इस बात को कह दूं, तो आप कह देंगे कि मुलायम सिंह जी आप तो हमारे वोट बिगाड़ना चाहते हैं। इस बात को आप अकेले में कहेंगे, सबके सामने स्वीकार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधान मंत्री जी का दिल बड़ा होता, तो जब मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीर पर बात नहीं करनी है, तो मैं पाकिस्तान जाने की बजाय मैं यहीं नहर वाली हवेली को खरीदकर रहूं, तभी प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए था कि नहर वाली हवेली में क्यों आप पाकिस्तान को हिन्दुस्तान में मिला दो और रेस कोर्स रोड पर रहो। यह पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि वहां चाहे कोई शासक हो, तानाशाह हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ शासक हो या फौजी शासक हो, कोई भी हो, वह वहां की कट्टरवादी ताकतों के दबाव में रहता है। इसलिए यह प्रश्न उनके लिये जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान का कोई तानाशाह शासक हो, लोकतांत्रिक हो या फौजी शासक हो, वह इस बात को जानता है कि कश्मीर को भारत से लड़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को नवाज शरीफ ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री गुजराल के सामने स्वीकार किया था और मुशर्रफ साहब कितनी भी घुड़की देते हों, लेकिन वे भी जानते हैं कि युद्ध के माध्यम से वे कश्मीर को नहीं ले सकते। जब मैं इसी बात को कहता हूं, तो आप कहते हैं कि मुलायम सिंह वोट बिगाड़ना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो फिर कहता हूं कि मुशर्रफ साहब यदि पाकिस्तान हिन्दुस्तान में मिला दें, तो नहर वाली हवेली क्या वे रेस कोर्स रोड पर रहें। यह बात अकेले आपके चौड़े दिल होने से नहीं बनेगी, बल्कि पाकिस्तान का भी चौड़ा दिल होना चाहिए। संकीर्णता छोड़नी चाहिए। दोनों तरफ जब चौड़े दिल होंगे, तब यह बात बनेगी। ...(व्यवधान)

हम खुलकर कहना चाहते हैं कि मुशर्रफ यदि पाकिस्तान को हिन्दुस्तान में मिला दें, तो वे रेस कोर्स रोड पर रहें, उन्हें नहर वाली हवेली में रहने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री विणु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : क्या आप चाहते हैं कि भारत का प्रधान मंत्री वहां का प्रधान मंत्री बन जाए, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए ? मैं फिर कहता हूं कि हिन्दुस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। जहां हमारा बलिदान हुआ वह कश्मीर हमारा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, प्लीज़ आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : â€¦(व्यवधान) हम फिर दोहराना चाहते हैं कि अगर वह हमें पाकिस्तान दे दें तो आ जाएं, कोई बात नहीं। मैं तैयार हूं। है दिल? वे नहर वाली कोठी में क्यों रहना चाहते हैं? दें पाकिस्तान, मिलाएं हिन्दुस्तान,पाकिस्तान, एक कर दें। पर वे इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। हम उन बातों में जाना नहीं चाहते, ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने ही हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा करवाया है। इसके लिए अकेले जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, ऐसी मानसिकता वाले अन्य लोग भी जिम्मेदार थे। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बंटवारे का अपराधी कौन है, इसमें मत पड़िए। हम कहना चाहते हैं कि जब तक दोनों तरफ से वोट का लालच दूर नहीं करेंगे,

तब तक दोनों एक नहीं हो सकेंगे। â€¦(व्यवधान) हम जानते हैं कि असत्य बोलने में वह कितना माहिर हैं। श्री क्लिंटन को चिट्ठी लिखिए। किताब में आग लगा दें, है हिम्मत? â€¦(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय : श्री क्लिंटन भारत में खुद आए थे, उन्हें किसी ने पुकारा नहीं था। और भी आएंगे। यह अटल जी के नेतृत्व में हुआ।â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। ये बीच में टोका-टाकी करते हैं। इनको फिर बुरा लगेगा। कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बहुत थे, न बिचारों को चारों तरफ घुमाते थे। उस वक्त हम भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। कश्मीरी पंडित मेरे पास आए। हमारी सरकार ने उनको दस-दस हजार रुपये महीना दिया। फाइल मंगाइए। कश्मीरी पंडितों को दस हजार रुपये महीना और हमने नोएडा में उनके रहने की व्यवस्था के लिए बातचीत शुरू कर दी थी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए। कश्मीरी पंडितों से पूछें कि हमारी सरकार जो रुपये देती थी, वह क्यों बंद कर दिए गए। चार साल से दस हजार रुपये क्यों बंद है? कश्मीरी पंडितों की बहुत बात करते थे कि जिस दिन अटल जी, आडवाणी जी प्रधान मंत्री बन जाएंगे, कश्मीर समस्या चुटकी में हल हो जाएगी। प्रधान मंत्री जी, आपकी चुटकियां टेप्ड हैं। अब ऐसी चुटकी बजनी जाने कहां बंद हो गई। कश्मीरी पंडितों की बारह साल से बहुत दुर्दशा है। पति-पत्नी, बेटा, बेटी सब किसी तरह टैंटों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की यह जिन्दगी है। बड़ी बात करते थे, चुटकी में कश्मीर समस्या हल होती थी। अब बताइए, चुटकी कहां गई। हम यह बात नहीं कहना चाहते। हम ऐसा कमजोर भी नहीं करना चाहते। वह जो यहां दहाड़ते थे, वे कहां चले गए। कौन दबाए हैं आपको, क्या मजबूरी है?

आप कभी-कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि राट्रपति ओथ भी नहीं ले पाये और आपने बधाई पहले ही दे डाली। यह पता नहीं है कि कौन आपको समझा रहा है या आप अपने मन से काम कर रहे हैं कि जल्दी-जल्दी बधाई दे दो। वह बधाई से काबू में नहीं आ सकते हैं। हम यह भी नहीं कहते कि ऐसे मौके पर क्या करना है। आपको बात भी करनी पड़ेगी और सीमा को सुरक्षित भी करना पड़ेगा। अब एक इंच भी जमीन आपकी बातचीत के द्वारा जाती है तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और बातचीत में यह सब हो रहा है। एक तरफ गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं,दूसरी तरफ बातचीत हो रही है। आप मुशर्रफ साहब को सबसे पहले बधाई देते हैं, जब दुनिया के देश आलोचना करते हैं। उनको कोई राट्रपति की मान्यता देने को तैयार नहीं है तो हमारे भारत के योग्य प्रधान मंत्री उनको सबसे पहले बाकायदा मान्यता दे देते हैं । लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई होगी तो यह नहीं कहा जायेगा कि उसका आन्तरिक मामला है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में रहेंगे, चाहे वे दुनिया के किसी मुल्क में हो। यह हमारे देश की विदेश नीति है। आप विदेश मंत्री रहे हैं। जब विदेश नीति बनी तो हम लोगों ने ये सारे सिद्धान्त बनाये थे, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने में बने हों और हमें इस बात का फर्क है कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति नेहरू जी, गांधी जी की देख-रेख में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी, तब, जब वे विदेश सचिव थे। विदेश नीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करिये, बातचीत करिये, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, दुनिया के लोगों का इन्तजार कर लेते। बातचीत तो होनी ही थी, चाहे वह जनरल रहता, चाहे राट्रपति रहता, लेकिन आपको सबसे पहले बधाई देने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए हमारी विदेश नीति की जो मान्यता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, वह जो हमारी विदेश नीति का अंग है, प्रधान मंत्री जी, उस पर कुठाराघात हुआ है, इसलिए आज हम कुछ बातों को खुलकर बोल रहे हैं। बुरा लगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि तब अच्छी तरह से जवाब भी मिल जायेगा। मैं इसलिए ये बातें रख रहा हूं कि यह सब देश के सामने साफ हो। â€¦(व्यवधान) आगरा की बातचीत पूरी तरह से असफल हुई। हमारा मीडिया भी सही नहीं रहा। कोई तैयारी भी नहीं और पहले से कोई एजेण्डा भी नहीं। सारी दुनिया नजरें लगाये बैठी थी कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान की बातचीत हो रही है। पाकिस्तान हिन्दुस्तान की जनता के बीच प्रत्येक घर में लोग उम्मीद लगाये बैठे थे, उनकी भावना थी कि दोनों में दोस्ती हो, लेकिन पता नहीं कि इनका बातचीत करने का तरीका क्या था। जैसे लोग कहते हैं कि पता नहीं कोठरी में आप क्या करते रहे। दोनों लोगों के बीच क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन बातचीत असफल हुई। आप कह रहें हैं कि साझा एजेंडें पर दस्तखत तो नहीं हो पाये, लेकिन बातचीत असफल नहीं हुई तो यह बता दीजिए कि बातचीत सफल कौन सी रही और असफल कौन सी । हम मानते हैं कि बातचीत असफल हुई। हमने आपको राय दी कि एक पंक्ति, एक लाइन ही लिखा लो कि अब हम दोनों भाई-भाई की तरह से बातचीत करेंगे, इस पर दस्तखत करा लो, बयान में तो आ गया और कोई भी विवाद होगा तो हम भाई की तरह बातचीत के द्वारा उसे सुलझाएंगे। तथा अब ताकत के बल पर, हथियार के बल पर हिन्दुस्तान पाकिस्तान की समस्या का निदान नहीं किया जायेगा। आप केवल यही एक लाइन लिखा लेते, अगर यह लिखा लिया होता, अब भी लिखाकर ले आइये तो हम पहले व्यक्ति होंगे, जो आपको बधाई देंगे। आप कम से कम यही काम कर लीजिए।

अध्यक्ष जी, बार-बार आपका इशारा हो रहा है, और नेताओं को भी बोलना है, आदरणीय सोमनाथ दादा को भी बोलना है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप बातचीत करें, बातचीत को हमारा पूरा-पूरा समर्थन है ।समर्थन पहले भी था, आज भी है, लेकिन बातचीत अपने देश के सम्मान एवं प्रभुसत्ता की कीमत पर नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात उठाता है तो आप दुनिया के सामने इसलामाबाद जाकर यह कहकर आएं कि हमारा जो एक चौथाई कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वह हमें वापस करे। मुझे उम्मीद है कि अबकी बार आप सावधानी के साथ जाएंगे और जाने से पहले पूरी तरह तैयारी करके जाएंगे। अगर जल्दी-जल्दी भागकर जाएंगे तो वह अच्छा नहीं रहेगा। आगरा में कोई तैयारी नहीं हुई थी, आपका मीडिया भी आपका साथ नहीं दे पाया। आगरा की वार्ता पूरी तरह असफल हुई है, विदेश नीति की कूटनीति असफल सिद्ध हुई है। मैं चाहता हूं कि जो कमजोरी यहां हुई, उसको वहां जाकर दूर करके आएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मुलायम सिंह जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वे यहां से क्या संदेश देना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी आपको मौका नहीं मिला है, जब आपको बोलने का मौका मिले, तब कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव : उनके साथ सीमा विवाद खत्म हो, यह हम चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान और भारत को एक करने की बात करते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपस में बात न करें। अब आप बैठ जाएं।

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): Mr. Speaker, Sir, the Agra Summit has left the country very confused. What is even more disconcerting is that even the hon. Prime Minister, the Government and the hon. Minister of External Affairs seem confused. They are not able to resolve this dilemma as to whether this Summit was a success or a failure.

The first reaction of the hon. Minister of External Affairs was: "In the Summit, we have made progress. We have embarked on a journey which is going to lead us to a destination called peace." Two days later, the Foreign Ministry disowns Agra as 'a bad dream'. Then, one day later, it is announced that the hon. Foreign Minister has accepted Mr. Sattar's invitation to visit Pakistan, "to pick up the threads from General Musharraf's visit", which has just been dismissed by the Indian Foreign Office as 'a bad dream'.

Sir, I do not think that the Government has ever received this sort of all-round support from all Opposition parties,

especially, the Congress Party. But as my colleague, Shri S. Jaipal Reddy very eloquently said that we almost gave them a blank cheque but they left us with a huge overdraft, and that is the balance-sheet of Agra.

The result is that we are left wondering about peace in South Asia. Was this another Lahorian "turning point in history in South Asia"? Has this placed us on the "high" road to peace or can it lead to another Kargil? Has the Agra Summit taken us forward or has it erased even the Simla Agreement which was our benchmark for almost three decades, and later the Lahore Declaration? Has Jammu and Kashmir become more secure, or will we, as we have in the last few days, witness many more innocents paying the high price for the Agra failure?

The jury is still out and we do hope that the Government will provide us with some answers to numerous questions that are agitating our minds.

In the recent history of our nation we have been subjected to some of the strangest twists and turns, especially over the last three years. The Government has launched many initiatives but each time we have regressed instead of going forward. We have tried to sprint but we have lost the very ground that we were standing on. Twice, the hon. Home Minister, with great fanfare launched what he called proactive initiatives in Jammu and Kashmir and the result was an increase in militancy. One fine morning, the Government launches a dialogue on Jammu and Kashmir by releasing the Hurriyat leaders. They put them on to centre-stage totally ignoring an elected Government and the Chief Minister there who is a member of their NDA. One year later, Shri K.C. Pant, discovers that the Hurriyat do not represent the people of Jammu and Kashmir! After coming close to giving visas to the Hurriyat the ruling coalition maneovours itself with great aplomb into a position where it had to boycott a Tea Party which was given in honour of a visiting guest who had come on their own invitation.

Life is indeed interesting and we are living in very interesting times. This flip-flop gains new height when dealing with Pakistan. When hon. Prime Minister, Shri Vajpayee took the bus to Lahore, we warned, "Take care before you leave or else you may seriously damage the future". We were not against a dialogue with Pakistan. We fully support it. The peace process must go on. The dialogue must go on at many levels. But in Lahore, into the summit, we seemed to rush totally unprepared and we know what the consequences were. Mr. Speaker, it would be well to remember what Talleyrand, the celebrated Foreign Minister of the Bourbons and Napoleon says. He said and I quote: "In diplomacy, by no means show too much zeal". We were brushed aside. We were told that the nation had arrived at a "turning point in history." But the PM's bus took a sharp downward turn and crashed down the slopes of Kargil. It was our Armed Forces who kept our honour intact. It was due to them that even today our flag flies proudly on the icy heights of Kargil.

One turning point led to another: 'No more dialogue with a dictator. No talks unless Pakistan stops encouraging cross-border terrorism'. But even as the Government ranted and raved about cross-border terrorism, it sent our esteemed hon. Foreign Minister to escort terrorists to their freedom in Kandahar. What an unprecedented spectacle that was. We hung our heads in disbelief and then the hon. Foreign Minister praises the Taliban, the very force that had connived with the hijackers. Our naivety and faith in human kindness is indeed touching!

But this was by no means the end of the fare. The proactive approach in Jammu and Kashmir which has been made proactive not once but twice, was suddenly jettisoned. The Government took an about turn to announce a unilateral cease-fire in Jammu and Kashmir and then promptly went into a deep slumber treating the cease-fire almost as an end in itself instead of a means to an end -- the end being the objective of establishing peace through dialogue. This euphoria did not last even six months. The cease-fire was suddenly called off. The pro-active approach was resumed again. But now there was not one but two U-turns which were simultaneously performed. Mr. Speaker, Sir, making two U-turns is a very deft manoeuvre. It is not easy. But given this Government's experience in U-turns, it was performed with consummate ease. The end of the cease-fire almost coincided with the invitation to General Musharraf. We have now completed the full circle. We are now willing to talk to the military dictator who is still supporting terrorism. With this track record, we now approach Agra.

I think, I can speak for everyone that we are extremely disappointed that Agra was a failure. We wished you success. We were with you in spirit. We were wishing you well. But where we are disappointed that Agra is a failure, we are certainly not surprised that it was a failure. We find this Government constantly whistling in the dark, waiting for some manna from heaven which would deliver. The Government suddenly woke up one day and like a budget traveller, they took the flight to Agra without even checking properly what they had taken in their bags. Mr. Prime Minister, you did not seem to be prepared for the journey that you had chosen to embark on. Agra was one of the rare Summits which will go down in history as one where confusion on the very agenda was allowed to prevail till the eve of the Summit. Should not some prior, behind the scene diplomatic activities and efforts have been made to ensure that a broad agenda was drawn up which would suit both the countries?

The hon. Minister of External Affairs tells us that they did tell the Pakistanis that they want to send the delegation to discuss and that the Pakistanis were reluctant. But if so, why did we rush into fixing a date? Why first an invitation and then a preparation? Most countries ask their Foreign Ministers and their Foreign Offices to create a broad

basis before an invitation is sent.

Sir, I was reading today an interesting article by my colleague Shri Mani Shankar Aiyar in which he talks about Rajiv Gandhi's visit to China. He says:

> "The first: to push an eyeball-to-eyeball military confrontation with the Chinese army at Sumdorongchu where we had apprehended a Chinese intrusion. It was the Chinese who blinked. "
>
> He further says:
>
> "Then came the February 1987 grant of full statehood to Arunachal Pradesh, notwithstanding the anticipated squawk from Beijing, indeed with every intention of signalling the People's Republic that every inch of Arunachal was Indian, whatever the Chinese might think.
>
> Thereafter, and only thereafter, were dates discussed for the visit to China. It was no coincidence that visits to both China and Pakistan were scheduled in the same month of December 1988. Everything was prepared down to the last detail before Rajiv Gandhi embarked for Beijing. Everything, therefore, went without a glitch.

17.00 hrs.

> "The one thing not planned for was Deng Xiaoping"""""s handshake before the cameras of the world in the Great Hall of the People. It went on and on and on. Every television viewer everywhere in the world was informed that the era of confrontation was over, the era of cooperation had begun. A decade later, the reverberations of that handshake are still echoing in the chancelleries of the world. This is what summits between adversaries should be about."

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Did you regain the lost territory?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : I beseech hon. Members to treat this with a little more seriousness.

Broad drafts are agreed upon before leaders of two hostile nations even shake hands before the camera. The summit is usually the finale to hectic diplomatic activity and exchange of views that precedes. Here the time tested practice was stood on its head. The desire for dialogue with Pakistan was right; it is correct; it must be pursued. But your implementation, if I may humbly say, was amateurish and no careful assessment was made as to why Pakistan was coming, what was their objective, and what was their strategy. If Pakistan had refused to look at the structure, if Pakistan had refused to look at an agenda, the dates should not have been finalised. What was the urgency to go into the summit without a structure, without an agenda?

This gives rise to much speculation. Was there pressure from other quarters? Was it to deflect from the dismal failure of the cease-fire? Was it to divert attention from the disastrous results in five State elections or was it Tehelka? I do not subscribe to that. I cannot imagine that the Government would be forced to gamble with the foremost challenge that we face in our foreign policy. But I am saying that this gives rise to a lot of speculation because the approach was so amateurish that you left yourself totally open.

We fully support, as I said, the dialogue at different levels. But the need for a dialogue does not mean that you go in for an ill-prepared one. It is absolutely shocking that after one day of the Prime Minister"""""s deliberations, after two one-to-one meetings, we hear Gen. Musharraf telling us that militants from across the border are not terrorists, but freedom fighters. What a remarkable intermission! In a summit that is initiated by us, our own core issue is rubbished by the other Head of State. Did we have to reach Agra to discover that Pakistan was not willing to talk about cross border terrorism?

The Prime Minister"""""s statement today said:

> "We had to abandon the quest for a joint document mainly because of Pakistan"""""s insistence on the settlement of Jammu and Kashmir issue as a pre-condition for the normalisation of relations. Pakistan was also reluctant to acknowledge and address cross border terrorism."

Did we have to go to Agra to discover this? What was the Foreign Office doing? I cannot blame the Foreign Office because you did not give them time. You did not give them time because you forwarded the invitation before they could get to work and prepare properly for such a high level summit. The very absence of the agenda allowed Gen. Musharraf to take far more advantage of the Agra summit than we could. As if this was not enough, the confusion continued into the summit.

The entire nation wanted to know how far India had gone on what was called very eloquently the "high road to peace." Whereas on the one side the Pakistan Foreign Secretary, Spokesman, Information Secretary and PIO were always available for formal and informal briefings, the members of the Indian Delegation seem to have suddenly disappeared into their burroughs. The hon. Foreign Minister says that he had gone to Agra to conduct diplomacy and not for a public relations exercise. Mr. Speaker Sir, we are not living in the age of Richeliev and Mazarin but we are living in the 21st century where sound diplomacy must be backed by sound communications and media strategy. This is crucial to diplomatic success.

General Musharraf utilises the media instrument to great effect. The television and newspapers churned out reams and reams of footage and columns of what the Pakistan position was. At the end, we are all familiar with the Pakistan position. But what was the Indian position, what was the Indian point of view, what did the hon. Prime Minister and hon. Foreign Minister want from the Summit, it was difficult to know it. It is because we hardly got a glimpse of the heroic duo. Only the heroine made a brief guest appearance - I do not know on whose invitation − and created a bedlamâ€¦ (*Interruptions*)

The only way we could cope with General Musharraf's breakfast show was to release hon. Prime Minister's remarks made 24 hours earlier. How pathetic! We simply did not have a strategy or any fallback options to retrieve our position. Even the Indian journalists were forced to turn to the Pakistani officials to figure out what was going on. I am not saying that you engage in a media war, but subtle briefings from time to time and an approachability are extremely important. Were we silent because we had no strategy, because our vision was confused and clouded? Or were we quiet because we wanted to surreptitiously agree to something that the nation had not been prepared for? I am not casting aspersions on the motivation of this Government. My point is, through your strange handling of the Summit, you allowed perceptions to fuel rumours and apprehensions. If the Government says that the perceptions were misplaced, I am prepared to accept what my Government says. But I cannot absolve you of the blame for having allowed these perceptions to arise in the first place.

I have great respect for Shrimati Sushma Swaraj's oratory, eloquence and articulations. But why was she allowed to speak when it is an established practice that only the External Affairs Minister or the Foreign Secretary or an authorised official are there to state positions?

Hon. Vajpayee, in his statement, has said:

> "During these discussions, I emphasised the importance of creating an atmosphere of trust for progress on all outstanding issues including J&K."

Was the omission of the mention of J&K by Shrimati Sushma Swaraj in her briefing going to help create this atmosphere that you are talking about? It becomes even more relevant when the hon. External Affairs Minister says that she spoke with the authority of the Cabinet. The result of her wise words were to give rise to a perception that the Cabinet was divided.

Was this the case? If so, what was the cause of this disagreement within the CCS because such perceptions lower the prestige and credibility of the Government. This is what a respectable magazine like *The Economist* had to say: "It appears that the two leaders agreed that the Declaration should just refer to terrorism. But the hawks on the Indian side, apparently led by Shri L.K. Advani, the Home Minister, insisted on adding cross-border terrorism in order to nail down Pakistan's responsibility for allowing Islamic militants to cross into India from its territory. This was the deal-breaker for the General". This is giving rise to this sort of speculation in reputed magazines. So, we would like to know the truth. We will accept everything you say about the issue. The issue is too sensitive; it is too delicate. We do not want to play politics in this. But explanations and answers are certainly required.

All through, General Musharraf was clearly sending signals in all his pronouncements that someone in the Cabinet was sabotaging the Declaration. This was his attempt all the time. In his recent Press Conference in Islamabad, he is so effusive in his praise for Shri Vajpayee and Shri Jaswant Singh that it is almost used as if to indicate that the Summit has not failed because of them, because they were in agreement. The subtle indication, or I may say, not so subtle indication, is that there were some others behind the scene. He says that he spent 90 per cent of his time talking about Jammu and Kashmir. The Prime Minister also says in his statement while talking about General Musharraf that in his presentation, President Musharraf focussed almost exclusively on Jammu and Kashmir.

Now, if this is the case and if 90 per cent of the time was spent on Jammu and Kashmir, where were our core concerns? How much time was left for our core concerns? General Musharraf then goes on to say in the Press conference: "Can there be a solution without resolving Kashmir? No. Certainly not." These are his words. "Other issues cannot be compared with Kashmir." These are all quotes from his Press Conference. "Simla and Lahore do not recognise the centrality of Kashmir. Therefore, they are hardly relevant." He would not agree to anything unless Kashmir was made the core issue. He goes on to say that militants are freedom fighters and indigenous and have nothing to do with cross-border terrorism. Then, he asserts that there was progress and they almost reached an

agreement. In fact, chairs were placed, according to him, and the differences were minimal. Then, what happens? He does not know. He does not want to comment on it. One version, of course, doing the rounds is that we ultimately rejected our own draft. That is again rumour and I would not like to place credence in it.

Shri Vajpayee himself in his statement says that we did achieve a degree of understanding. But if this was true, then your signing, if General Musharraf is correct, which you can easily refute, would mean the following. It would mean that the centrality of the Jammu and Kashmir issue had been agreed to, and, it would mean that our core issue of cross-border terrorism had been relegated. What is the truth? This is what the country wants to know and that is why we find General Musharraf all the way through seems to be praising Shri Vajpayee and his open-mindedness. In fact, he is putting you into an embarrassing position.

In effect, he is trying to say that they both had agreed − somebody else had not − to these things and if they had agreed, then it had to be on these two premises; otherwise, he would have walked out. I am not the one saying that this is factually correct. But the hon. Prime Minister had said in his musings from Kerala and I quote:

> "In our search for a lasting solution to the Kashmir problem, both in its external and internal dimensions, we shall not traverse solely on the beaten track of the past. Rather, we shall be bold and innovative designers of a future architecture of peace and prosperity for the entire South Asian region. In this search, the sole light that will guide us is our commitment to peace, justice and the vital interests of the nation."

This is what the Prime Minister had said in his musings. This is what Gen. Musharraf keeps talking about in his Press Conferences, however inaccurate he may be. Please refute it.

Then, the Pakistan High Commissioner decides that it is his turn to speak. He says in a Press Interview on the 19th July and I quote:

> "A working understanding has definitely been reached to move on nine areas, three of these areas, Kashmir, CBMs and narcotics, have been selected to be dealt with at political level. Thanks to the understanding reached at Agra, Kashmir now gets the first place."

This is what the Pakistan High Commissioner had said. What is to be noted is that there is no mention of cross-border terrorism among the subjects to be dealt with at political level, according to the Pakistan High Commissioner's version. Is not even the Lahore formulation agreeable? The Lahore formulation says:

> "reaffirm their condemnation of terrorism in all its forms and manifestations and their determination to combat this menace."

Is even this not acceptable?

Sir, Simla was the bedrock of bilateralism and Lahore was an extension. Both Simla and Lahore mentioned Jammu and Kashmir as just one of the issues. Gen. Musharraf's main grouse was that he wanted Kashmir as the core issue. Everyone knows that and that without that, he would not sign a Declaration. When he says that they had almost signed a Declaration, does it mean that the essence of the past agreements was frittered away? There is no contradiction to these Pakistani statements. There is no contradiction to the Pakistani Spokesman, Maj. Gen. Qureshi on Indian T.V. when he said:

> "That a draft was corrected by hon. Jaswant Singh and shown to Shri Atal Bihari Vajpayee."

You contradict him if it is not correct. What is your Foreign Office doing? Is it asleep? They are getting away with creating such impressions internationally.

Sir, as far as the draft is concerned, what did the Prime Minister say in his statement? He eventually, however, said something about a draft. He said:

> "Despite the obvious differences in our perspectives, we made progress towards bridging the two approaches in a draft joint document."

A few days earlier, on July 23rd, in *The Hindu*, there is this headline, which says: "There was no draft agreement, says PM." "He made it clear that at no point were the two leaders, Gen. Musharraf and himself, 'ready to sign' an agreement, for 'no draft came before us'." In his statement he is saying: "ultimately we had to abandon it." So, what is the truth? I ask this because confusion is still reigning supreme. Were they close to signing or agreeing to elevate Kashmir as the prime issue with no reference to cross-border terrorism? Would this allow for a future Pakistan rejection of agreements arrived at Simla and Lahore?

Since this was against the political consensus, the Government should explain if it came close to unilaterally

breaking this consensus. Let us know the areas of agreement and the areas of disagreement. Are General Musharraf and Shri Qazi, High Commissioner, misleading us? How was the Pakistan version freely allowed to gain currency? Look at the impression in various journals. I just read out the *Economist* to you. The *Far Eastern Economic Review* has the same sort of impression. These are the impressions that have gained ground because the pronouncements emanating from Pakistan at different levels were never contradicted immediately. Our correct version should have been established in the public mind.

I am fully prepared to accept hon. Prime Minister's word as I certainly trust his word - the Prime Minister of my country's Government - before any other Head of State. All I am saying is that we need answers. Take the nation into confidence and build a consensus. Give us the true version. We will accept it. We cannot allow and you cannot allow General Musharraf to have a field day at your expense because it will be at a heavy cost to the nation.

As far as the Summit is concerned, we lost before the Summit, we lost during the Summit and we have lost after the Summit. We lost before the Summit because General Musharraf did not want an agenda. This was his ploy. If there had been a structured agenda, he could not have kept merely pushing 'Kashmir' − Jammu and Kashmir − in the discussions. He did not want an agenda. We gave in. We lost during the Summit because they were more articulate and more communicative. We have lost after the Summit because of the international impression that the Cabinet is divided, and that the country was confused. I hope that we are communicating now.

Sir, a Summit between two Heads of State is a double-edged weapon. If planned with rigour and panache, it has the potential of bringing the most hostile nations together. But if messed up, it can widen the gulf, create gaping chasms and unleash forces that are vigorous in violence.

Agra has pushed us backwards and not forward. Look at the heinous attacks that are taking place for the last three days. Thirty-three people have lost their lives in Doda and Sheshnag. Killings are taking place as a direct result of the hamhanded handling by this Government. This Summit has failed and indirectly encouraged the militants. The blood of innocent people was spilt at Pahalgam last year. The Hizb-ul-Mujahideen and the Lashkar-e-Toiba, while extolling General Musharraf, have announced an acceleration in their activities and Pakistan is bound to encourage them. Rather than weakening cross border terrorism, the failure of the Summit has strengthened it. But General Musharraf regards these barbaric terrorist acts as a part of an indigenous freedom struggle. In his Press Conference in Islamabad, he said:

> "If we do not sign an agreement, it is possible that some extremist elements will get encouraged. However, if progress is made, then, these elements can be controlled. "

What does he imply? Dealing with Pakistan is dealing with very hard-nosed diplomats on whom poetry and sentiments have little effect in the final analysis.

One cannot just overlook General Musharraf's career background. He is reputed to have had associations in his early days with the Tabligh Jamat and Lashkar-e-Toiba. He was the Force Commander of the Northern Area that covered the entire operations in northern India, including Siachen. He has moved into Government, hard-liners from the Zia regime. Is he now pointing a gun to our head that only if we had made progress, they could be controlled? This is the same General Musharraf of the Kargil tapes that were leaked out.

In a telephone conversation from China with Gen. Aziz he had said, and this is a taped conversation that was leaked. He said, "the militants are like a tap in Pakistan"""""s hands, they can turn it on or they can turn it off whenever they want." Then where is the meeting point? Gen. Musharraf in his Press Conference has said that the result of the freedom struggle is Agra. Now, if PM goes to Pakistan, does it mean that this stepped up militancy has made him battle weary, has made him fatigued and that is why he is going to Pakistan? Is this the courtesy that Gen. Musharraf is showing to our Prime Minister?

Therefore, in the end, I would just like to suggest certain steps that should be taken. I agree that great care should be taken before going to Pakistan. By all means, have meetings in the margin at the United Nations or at SAARC. Their officials should meet, their Foreign Ministers should meet. Hon. Prime Minister, I beseech you, do not go to Pakistan without defining the structured agenda and without being fully prepared. I urge you to build consensus on the approach that you wish to adopt, a consensus within and outside the Government. You cannot afford to be media shy and go underground. The age of diplomacy in the classic mould is over. You must articulate our view points with boldness and candour because you have said in your statement, "we are not looking for propaganda advantage or seek to secure debating points, we will engage in quiet, serious diplomacy".

Mr. Prime Minister, this unilateral chastity will not do. It has to be a two-way street and therefore, we should put-forth our views on Jammu & Kashmir with conviction. It is an integral part of India and there can be no compromise on this. Pakistan"""""s abetment of cross border terrorism must stop.

Sir, a most important issue is the nuclear one. How much emphasis have you laid on this? It is a matter of great regret. So if you do ultimately, after preparing yourself, go to Pakistan, you must raise this as one of the most vital issues because two nuclear powers have a very heavy responsibility. Even when the erstwhile Soviet Union and the United States were eyeball to eyeball, their discussions on the nuclear issue, their dialogue never ceased. Therefore, Nuclear Risk Reduction measures must be put into place and they should be treated independently whether your talks in the other matters succeed or fail. There should be a different track for this. I would urge you to put in place a machinery which can meet from time to time, exchange views, talk about safety measures and create a greater comprehension, at least, on this particular issue because the whole sub-continent is interested, all our neighbours are interested.

I would not like to go into much more detail on how to deal with Pakistan. This is the Government"""""s prerogative. I have just suggested certain essential general contours, but I assure you that the Congress Party will always support any genuine initiative this Government wants to take for peace with Pakistan. The Government must take care, however, to be prepared. There must be no repetition of Agra because the cost of failure is too high and can imperil many precious lives.

Undoubtedly, another aspect that has come forth in these last few days is that there is yearning for peace amongst the people of India and the people of Pakistan. We cannot continually frustrate these high sentiments far beyond a point. If frustration sets in, it would breed cynicism and that could convert into a yearning for war and what a result of that can be between two nuclear nations. It is too horrendous to envisage. You have the responsibility, Mr. Prime Minister, to ensure that an environment is created where use of such weapons is never dreamt off. Therefore, treat it on a different track and do not get it meshed up with these other very comprehensive and very complicated issues. It must be a separate track must be a separate track because the safety and security not only of India and Pakistan but the entire sub-continent, all our neighbours, is very much dependent on it.

So, how does the final Agra balance-sheet 2001 compare with the situation in 1998? First, Jammu and Kashmir has virtually been portrayed wrongly or rightly as the central issue. Secondly, Pakistan has now described cross border terrorists as freedom fighters. Thirdly, they have virtually declared Shimla and Lahore as redundant. Fourthly, militancy has greatly increased. Fifthly, the Pakistan High Commissioner had the gall to declare on Indian TV, on Indian soil --and I commend and compliment Shrimati Sushma Swaraj for the way she took him on--that he does not recognise the leader of the duly elected Jammu and Kashmir Government, Shri Farooq Abdullah as the Chief Minister. The High Commissioner is saying this on Indian soil, on Indian TV. This is the result of your three years culminating in your enthusiastic negotiations with the same General Musharraf, who, in an interview, to *Khaleez Times* had said and I quote: "Of course, in national interest, sometimes you have to tell a lie."

It is not a balance-sheet that can make any Government proud and the Agra type, half-baked, ill-prepared exercise has only aggravated the situation.

Congress is prepared to support you in a well thought-out and strategic peace effort but such naïve and amateurish efforts cannot earn you the respect or support of the country. Our wholehearted support for any peace effort but for Heaven's sake, be more meticulous, be more prudent in the conduct of our foreign policy.

You have done some harm to the credibility and the image of our country. The Indian political establishment and the people would support the right overtures of peace with its neighbour. However, they would react firmly and decisively if chicanery is dished out in the garb of peace and that is what you have to guard against when you talk to Pakistan and when your dialogue continues with Pakistan.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आगरा शिखर वार्ता पर अभी मुलायम सिंह जी और माधवराव सिंधिया जी ने यहां अपने भााण दिये। मैं समझता हूं कि जो वातावरण शिखर वार्ता से पहले सर्वदलीय नेताओं की बैठकों में पैदा हुआ था, आज उसके बिलकुल विपरीत भााण दिए गए। माधवराव जी ने सिखाने की कोशिश की है कि शिखर वार्ता कैसे होनी चाहिए, वार्ताओं में क्या काम करना चाहिए, वार्ताओं की क्या तैयारी करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जिस पार्टी ने 60 हजार वर्गमील भारत का हिस्सा चीन के हाथों में दे दिया, जिस पार्टी ने एकतिहाई कश्मीर अधिकृत रूप से पाकिस्तान के कब्जे में दे दिया हो, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 93 हजार कैदियों को छोड़ दिया हो, जिस पार्टी ने सेना ने अपना खून बहाकर पाकिस्तान के जीते हुए हिस्सों को शिखर वार्ताओं में लौटा दिया हो, जिन्होंने सारी शिखर वार्ताओं में हमेशा पाकिस्तान की शर्तों पर समझौता किया हो, उस पार्टी के लोग और वे हमें आज बता रहे हैं कि शिखर वार्ताएं कैसे की जाती हैं।

अध्यक्ष जी, 93 हजार कैदियों को जिस पार्टी के नेता ने छोड़ दिया हो और उसके बदले अपने देश के 54 सैनिक कैदियों को पाकिस्तान से नहीं छुड़ा पाए, वे आज हमें सिखा रहे हैं कि शिखर वार्ताएं कैसे की जाती हैं। जब पाकिस्तान हार चुका था, पाकिस्तान पराजित हो चुका था, तब भुट्टो साहब ने शिमला शिखर वार्ता की जिसमें हमारे देश की उस समय की नेता ने उनके कैदी भी छोड़ दिए, हमारी सेना द्वारा अपना खून बहाकर जीती गई जमीन, जो हमारी सेना की भारी उपलब्धि थी, वह भी पाकिस्तान को वार्ता की मेज पर प्लेट में सजाकर वापस कर दी, उस पार्टी के नेता आज हमें शिखर वार्ता कैसे होनी चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे होनी चाहिए होती है, हमें अलंकारिक भााा में बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि आज मुलायम सिंह जी को क्या हो गया, वैसे मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमति जताता रहा हूं, लेकिन आज वे ऐसी भााा में बोले जिसे मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने अखंड भारत की बात कही।

वे आज अखंड हिन्दुस्तान की बात कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मिला दो। जब कभी हम अखंड हिन्दुस्तान की बात करते थे तो नेहरू जी से लेकर आखिर तक हमको कहा जाता था कि ये साम्प्रदायिक हैं, ये दंगे कराना चाहते हैं, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान में लड़ाई कराना चाहते हैं। आज इन्होंने यहां इस तरह की बात

रखी।â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने महासंघ की बात की और आज भी कह रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके गृह मंत्री जी दो बार महासंघ की बात कह चुके हैं। यह बात औरों से कीजिए।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उन्हीं से बात करता हूं क्योंकि आप तो हमारी भााा बोल रहे थे। मुझे माधवराव जी पर आश्चर्य होता है। वे इसपर विश्वास कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने क्या कहा, वे विश्वास कर रहे हैं कि काज़ी साहब ने क्या कहा, वे विश्वास कर रहे हैं कि उनके विदेश मंत्री ने क्या कहा। वे हमारे विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। वे उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं कि भारत ने अपना रुख कैसे रखा। उहोंने बीच में कहा कि एकदम गायब हो गए और श्रीमती सुामा स्वराज ने वहां जाकर क्या बात रखी थी, क्या कहा, और यह कहा कि उससे बात बिगड़ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपने बहुत बड़ी बात की है और यह कहा है कि पाकिस्तान को बता दें, वहां जाने से पहले यह करें, वह करें। जिस दिन सर्वदलीय नेता बुलाए गए थे, उनमें से सब नेता यहां बैठे हैं। माधवराव जी का मैं नहीं जानता परन्तु वहां हरेक ने कहा कि प्रधान मंत्री जी को पाकिस्तान में जाना चाहिए, किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए। उनको बता दिया गया था। अगर पाकिस्तान वहां एजैंडा न मानने को तैयार हो। मुझे मालूम है कि शिखर वार्ता से पहले भी बुलाया गया था। सभी नेता वहां मौजूद थे। â€¦(व्यवधान)शिखर वार्ता से पहले भी बुलाया गया, जब आगरा जाने से पहले सभी दलों के नेता उसमें आए थे।â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : चिट्ठी से पहले नहीं।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : जी हां, वह ठीक है, चिट्ठी से पहले नहीं। उससे चार दिन पहले बुलाया गया।â€¦(व्यवधान)पहले बुलाना चाहिए था। प्रधान मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने इस बात को स्पट किया परन्तु चार दिन पहले जब बुलाया गया था तो क्या उसमें यह नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान कोई एजैंडा मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान कोई स्ट्रक्चर्ड डिबेट के लिए तैयार नहीं है? क्या उस समय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, श्री चटर्जी और मुलायम सिंह जी को यह नहीं बताया गया कि वे यह कह रहे हैं कि हम जिस दिन भारत आएंगे, यहां पहुंचेंगे, तब अपना एजैंडा बताएंगे? तब तो किसी ने नहीं कहा कि बातचीत तोड़ दें, तब तो किसी ने नहीं कहा कि उनसे वार्ता मत करो। हरेक ने वहां यह रिपीट किया कि पाकिस्तान न भी करे परन्तु आप वार्ता करें। उस वार्ता में क्या करें। उसमें एक कनसैन्सस बना, सबने मिल कर कनसैन्सस बनाया और वह कनसैन्सस क्या था, यह आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सोनिया जी ने बहुत स्पट शब्दों में कहा कि इसका आधार शिमला समझौता और लाहौर समझौता होना चाहिए।â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने यह कहा कि कुछ भी न हो, एक पंक्ति यह लिखवा लें। मुलायम सिंह ने कहा कि कम से कम एक पंक्ति यह लिखवा लीजिए। सदन के अंदर इधर-उधर की बात मत कीजिए।

MR. SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, he is not yielding. Please sit down.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : शिमला समझौते, लाहौर समझौते के पैरामीटर में बात कीजिए, यह कांग्रेस पार्टी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं बोला था तो मैंने कहा कि उन्होंने यह बात बिल्कुल ठीक कही है, इसका ध्यान रखना चाहिए। सबने कहा, आपने भी उस बात को कहा कि क्रॉस बार्डर टैरोरिज़्म हमारा कोर ईशू होना चाहिए। तीसरी बात आपने कही, मैंने बात की थी, आपने उसे रिपीट किया कि हमारे कैदियों को जरूर छुड़वाना, कैदियों के लिए उनसे बातचीत की जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा कि इसके साथ-साथ गरीबी, भुखमरी, बोरोजगारी, इन सारे सवालों और व्यापार के मामले में बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद यह कहा गया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसके ऊपर एक इंच जमीन देने की बात नहीं की जानी चाहिए, समझौते के अंदर इस बात को न किया जाए, यह हमारा ईशू होना चाहिए। फिर उनसे यह कहा गया कि पाकिस्तान से बात करते हुए पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे और मंदिर हैं, उनकी बात भी कर लेनी चाहिए।

यह सारा कन्सेंसस वहां पर बना। इसको रिपीट किया गया और मुझे बताइये कि क्या प्रधान मंत्री जी ने इनमें से एक भी बात को छोड़ा, इनमें से सब बातें कहीं या नहीं कहीं? श्रीमती सुामा स्वराज ने जो ऑथोराइज तौर पर आकर कहा, उसमें उन्होंने यही बातें रिपीट कीं कि प्रधान मंत्री जी ने इन सब बातों को दोहराया है, क्रास बोर्डर टैरेरिज्म को दोहराया, गरीबी और भुखमरी की बात को दोहराया, व्यापार की बात को दोहराया। इसके साथ पाकिस्तान के अन्दर गुरुद्वारों और मंदिरों का सवाल उठाया, 54 लोगों को छुड़ाने की बात की है और इसके साथ आणविक शस्त्रों के बारे में दोनों देशों में युद्ध न हो, इसकी बात की है और लाहौर और शिमला समझौता इसका कोर होगा, यह बात की है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बजाय यह कहने के कि सारा देश प्रधान मंत्री जी को बधाई देता है और उस दिन कहा गया कि आपने पाकिस्तान के मुशर्रफ को खाली हाथ लौटा दिया, एजेण्डे के ऊपर एक बात पर भी सरेण्डर नहीं किया, यह पहली बार है, मैं यह कहना चाहता हूंâ€¦(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : मल्होत्रा जी, निमंत्रण देने के पहले ही एजेण्डा तय करना चाहिए था।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please do not disturb.

...(*Interruptions*)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : यह पिछले 50 साल में पहला प्रधान मंत्री है, जिसने पाकिस्तान की शर्तों पर समझौता नहीं किया, जिसने मुशर्रफ को खाली हाथ लौटा दिया, हिन्दुस्तान की एक इंच जमीन नहीं दी, हिन्दुस्तान का कोई कन्सेशन उसको अपने एजेण्डे के बाहर नहीं दिया। â€¦(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माधव राव जी बार-बार यह बात कहते रहे - मैं विश्वास नहीं करता, पर ये बातें अखबारों में छप रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं कि क्या आपने न्यौता किसी बाहर वाले के कहने से दिया था। मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रणव मुखर्जी साहब ने जब डिस्कशन हुआ तो अपने भााण के अन्दर क्या कहा। अब प्रणव मुखर्जी साहब और माधव राव जी की बातचीत में फर्क हो तो मैं नहीं जानता

*He said:

> "Therefore, you convey the message to them and rightly the message has been conveyed. But how can this message be understood in its proper perspective if in the next breath it is suggested that unless the

> military regime of Pakistan gives a commitment to stop cross-border terrorism the dialogue will be meaningless, useless? Is it possible to have such a situation?"

वे पूछ रहे हैं कि ये शर्तें क्यों लगा रहे हो। अगर आप पहले अपनी बात में यह सब लगाते हो, यह प्रणव मुखर्जी साहब का 23.11.2000 का भाण है, जिसमें वे अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि वहां बड़ी मुश्किल है, बातचीत बड़ी मुश्किल है, वार्ता बड़ी कठिन हैâ€¦(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : आप कहां से कोट कर रहे हैं?

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : यह पूरे का पूरा प्रणव मुखर्जी साहब का पार्लियामेंट में दिया गया भाण है।â€¦(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हाउस में?

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : जी हां, हाउस में हुआ है। उसमें उन्होंने आगे यह भी कहा है कि आप ये जो कह रहे हैं कि वहां पर मिलिट्री का शासन है तो मिलिट्री शासन से ही बातचीत होती है, इसके ऊपर ही आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे मालूम है कि डॉयलाग नहीं होगा, पर बातचीत करो, बिना शर्त के बातचीत करो। वहां पर पाकिस्तान में कौन सा शासन है, पहले भी पाकिस्तान में मिलिट्री शासन रहा है, जब कांग्रेस के लोगों ने बातचीत की थी। यह वे खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमेशा बातचीत होती रही है। वहां मिलिट्री शासन था, तब भी बातचीत होती रही है तो आज यह कौन सी नई बात पैदा हो गई। अगर हम कहें कि क्रास बोर्डर टैरेरिज्मâ€¦(व्यवधान) He further says:

> "I am afraid, Mr. Minister, if we do not take the initiative into our hands, we shall have to do this at the instance of others, which we would not like."

यह प्रणव मुखर्जी कह रहे हैं कि अगर आपने अपने हाथ में इनीशिएटिव नहीं लिया, आपने बिना शर्त बातचीत नहीं की तो फिर दूसरों के कहने से करनी पड़ेगी।

हम उसे पसंद नहीं करेंगे। आज आप खड़े होकर कह रहे हैं कि बातचीत क्यों शुरू कर दी, इनीशिएटिव क्यों लिया, तारीख क्यों तय कर दी। दुनिया में पाकिस्तान सबसे कह रहा था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हिन्दुस्तान तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि बातचीत क्यों नहीं करते, सी.पी.आई. (एम.) वाले भी कहते थे कि बातचीत करो, आज भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए, आप बातचीत क्यों नहीं करते। अगर हिन्दुस्तान की सारी पार्टियां कह रही हों कि बातचीत करो, दूसरे मुल्क कह रहे हों कि बातीचत क्यों नहीं की, प्रधान मंत्री जी ने इनीशिएटिव लिया कि अच्छा हम तैयार हैं बातचीत करो, पर उसकी शर्त पर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कह दिया कि हम एजेंडा नहीं रखते, तो क्या करें। माधवराव जी ने पांच-छः बातें यहां रखीं। एक बात यह भी कही कि आज अखबार में छपा है कि किसी के दबाव में बातचीत की जा रही है, यह भी कहा गया कि आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया।

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : I said that these are the perceptions which I do not believe.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : कहने का तरीका है, वह मैं भी जानता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि मैं विश्वास नहीं करता। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन अभी अमेरिका होकर आया है, जिसमें यह कहा गया कि इस डेलीगेशन में कई लोग प्राइमिनिस्टीरियल केंडीडेट हैं। यह अखबारों में छपा है कि ये वहां पर अमेरिकी सरकार को एश्योर्ड करके आए हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम प्रो-अमेरिकन एटीट्यूड रखेंगे। क्या आपकी तरफ से किसी ने इसका खंडन किया, क्या आपने इसके बारे में कहा कि यह गलत छपा है कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन मैं इसका विश्वास नहीं करता कि ऐसा कहकर आए होंगे। परंतु यह पर्सेप्शन है। दूसरी जगह कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हमारी सरकार बनने वाली है और हम प्रो-अमेरिकन एटीट्यूड रखेंगे।

हुर्रियत के बारे में कहा गया कि कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। चाय पार्टी हुई, हुर्रियत वालों से बात हुई। मुशर्रफ साहब ने बहुत सारी बातें अंतरराट्रीय शालीनता के खिलाफ की हैं। उनको बताया गया कि हुर्रियत से बातचीत न करो, लेकिन उन्होंने की। सिर्फ हुर्रियत से बातचीत ही नहीं, जम्मू-कश्मीर के महाराजा कर्ण सिंह को नहीं बुलाया, फारुक अब्दुल्ला को नहीं बुलाया, उन्होंने वहां के किसी चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं बुलाया। वहां से छः सांसद हैं, किसी को नहीं बुलाया और न वहां की असेम्बली के किसी सदस्य को बुलाया। उन्होंने यही कहा कि हुर्रियत ही एकमात्र वहां की प्रतिनिधि है तो हमारी एन.डी.ए. में शामिल सभी पार्टियों ने उस चाय पार्टी का बायकाट किया।

1748 hrs. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मुलायम सिंह यादव : मुशर्रफ साहब हुर्रियत वालों से बात करते रहते हैं, चार-पांच महीने हो गए, रोजाना बात होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हुर्रियत से बातचीत न करो, लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि अगर मुशर्रफ साहब हुर्रियत को केवल मात्र प्रतिनिधि घोाित करें और चाय पार्टी पर बुलाएं, यह ठीक नहीं है। मुझे थोड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने साधारण से प्रतिनिधि को वहां भेजा, जबकि वह भी नहीं भेजना चाहिए था। परंतु मुलायम सिंह जी आप सोनिया जी की चाय पार्टी पर जाएं या न जाएं, यह आपके घर का मामला है, लेकिन आप मुशर्रफ साहब की चाय पार्टी में कैसे चले गए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सोनिया जी ने हमें चाय पार्टी पर कब बुलाया, यह आपको पता नहीं है। हमें तो बुलाया ही नहीं गया। हुर्रियत वालों को जेल से आपने छोड़ा, आपने पासपोर्ट दिए और न जाने क्या-क्या कियाâ€¦(व्यवधान)जहाज में बैठाकर आप ले गए, उनके साथ जहाज में आपने खाना खाया। आप बताएं कि क्या आपने हुर्रियत के लोगों को जेल से नहीं छोड़ा, क्या आपने उनको पासपोर्ट नहीं दिए और क्या उनके साथ खाना नहीं खाया ?

सर्वदलीय मीटिंग में मैंने कहा कि अभी फैसला कीजिए कि वहां पर जाना है या नहीं जाना है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक घंटे में, दो घंटे में मुझे सूचना दीजिए कि क्या निर्णय है। क्या मुझे कभी निर्णय दिया? â€¦(व्यवधान)आप गलत क्यों बोल रहे हैं?â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मेरे लिए आपत्ति यह है,

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :एक बात खत्म नहीं हुई और दूसरी शुरू हो गयी।

â€¦(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : जेल से छोड़ने वाले आप हो, हीरो बनाने वाले आप हो। देश की जनता को आप गुमराह कर रहे हो।â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, what is this?

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If any hon. Member wants to seek any clarification, the convention is that the speaker has to first yield. The senior Members are interrupting here.

...(*Interruptions*)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने बोलते हुए एक शब्द भी इनके लिए नहीं कहा। â€¦(व्यवधान)मैं समझता हूं वार्ता उस दिन टूट गई थी और एक तरह से टूट जानी चाहिए थी जिस दिन उन्होंने कहा कि कश्मीर को केवल हुर्रियत रिप्रेजेंट करती है। दूसरे दिन वह नाश्ते पर बुलाते हैं और कहते हैं कि ऑफ दि रिकार्ड इनफॉर्मल डिसकशन है लेकिन उस डिसकशन को सभी टी.वी. पर दिखाया जाता है, बाहर उसे प्रकट कर दिया जाता है। यह दूसरी शालीनता उन्होंने तोड़ी। उन्होंने अन्तर्राट्रीय प्रोटोकोल को तोड़ा। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं, वे फ्रीडम फाईटर्स हैं। वहां पर जिस तरह से लोगों को मारा जाता है, जहां पर गला रेत-रेत कर काटा जाता है। पत्नी के सामने पति को मारकर उसके कलेजे निकाले जाते हैं और यह बात कोई साल दो साल में नहीं हो रही है, 1988-90 से हो रही है और लगातार आतंकवादी वहां पर किस तरह से भीाण अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, क्रूरतम हत्याकांड कर रहे हैं। वहां पर लोगों को रेत-रेत कर, डुबो-डुबो कर मारने की घटनाएं करते हैं और कल मैंने पढ़ा जिसमें यह कहा गया कि जब वे मार रहे थे तो मां ने कहा कि जो कुछ लेना है, हमसे ले लो लेकिन कम से कम इसकी जान छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हमें तो भारतीयों का खून चाहिए। हमें पैसे नहीं चाहिए। क्या भारतीयों का खून इस बात पर नहीं खौलना चाहिए कि उन्होंने आतंकवादियों को स्वतंत्रता का सैनानी कह दिया और आप आलोचना इस सरकार की कर रहे हैं? आप मुशर्रफ की आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान वहां आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा कि उनको दो टूक बताना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने यह भी कहा था कि वहां पर पाकिस्तान के जो अड्डे हैं, उनको तोड़ देना चाहिए और सही बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके अड्डे हैं, उनके ऊपर हमला करो, उनको तोड़ दो। आपने ठीक कहा था परंतु आश्चर्य यह है और होना यह चाहिए कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसमें सारा देश मिलकर एक आवाज में पाकिस्तान की निंदा करे और मुशर्रफ को बेनकाब करे। यहां पर तो मुशर्रफ महात्मा गांधी जी की समाधि पर शांति की बात कर गया था। उसके बाद इतने भयंकर तौर पर वहां कांड हो रहे हैं। आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन प्रो-एक्टिव की बात की थी, क्या दोनों सदनों में हाहाकार नहीं मचा था कि आडवाणी जी ने प्रो-एक्टिव करने की बात कर दी है और जब प्रो-एक्टिव की बात आई तो आप हाहाकार मचा दें। मुलायम सिंह जी उस समय वोट की बात आती है। आज वोट की बात नहीं आती है। प्रो-एक्टिव करने पर उन आंतकवादियों का पीछा करते हुए प्लानिंग से पहले उनको मारने की बात करें तो आप सब लोग विरोध करने लग जाते हैं और तब मानवाधिकार की बात उठानी शुरू कर देते हैं और तब कहा जाता है कि सेना उन पर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है तब मानवाधिकार के झूठे और घटिया बातें शुरू कर दी जाती हैं।â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप गलत बयानी मत कीजिए। मैंने यह कभी नहीं कहा। मैंने तो हमले तक के लिए कहा कि उनके कैम्पों पर हमला कीजिए।â€¦(व्यवधान)

माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी जी ने कहा है कि मत छेड़ो â€¦(व्यवधान)मुलायम सिंह को मत छेड़ो, उधर छेड़ो। â€¦(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : मुलायम सिहं जी, मैं आप ही की भाा बोल रहा हूं। â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप डायरैक्ट मुलायम सिंह जी की बात करना शुरु कर देते हैं। इससे सारी आपत्ति फेस करनी पड़ रही है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : ये भाड़े के हत्यारे पाकिस्तान से भेजे हुए हैं और पाकिस्तानी पैसे से उनके वहां पर अड्डे चलते हैं। "वाशिंगटन टाइम्स" में जो रिपोर्ट छपी है, उस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। The headline of the news is "1.75 Millions being Trained for *Jehad* in Pak : Report". It says:

> "About 1.75 million Pakistani youths are being trained in nearly 7,000 *madarasas* (religious schools) across Pakistan for waging the *jehad* (holy war) in Kashmir and other parts of the world according to *The Washington Times.* "

ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। क्या सारे देश को उसके खिलाफ विश्व भर में जनमत जागृत नहीं करना चाहिए। बजाय इसके कि आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यह कोई दो-एक दिन से नहीं हो रहा है । यह 1988 से पाकिस्तान की वजह से काश्मीर के हालात बिगड़े हुए हैं। क्यों बिगड़े, वे भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं â€¦(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : श्री जगमोहन जी आपके साथ बैठे हुए हैं। â€¦(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : जिस दिन उसने वहां कह दिया, लगभग उसके बाद पाकिस्तान से वार्ता नहीं होनी चाहिए। यह कहा जा रहा है कि हमें निराशा हुई, हम चाहते थे कि सक्सैसफुल हो जाती। यह दिखाया जा रहा है। माधवराव सिंधिया जी कह रहे हैं, मुशर्रफ वहां थे और वायपेयी जी यहां थे â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारे अटल जी जैसे लीडर, उस दिन थोड़े बौने लग रहे थे।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : पाकिस्तान के सारे राजनीतिक दल और पूर्व प्रधान मंत्री भी कह रहे है कि मुशर्रफ खाली हाथ वापिस आए हैं। दुनिया जानती है कि मुशर्रफ खाली हाथ वापिस आए हैं। इस सारे सदन में एक भी आदमी है, जो यह कहे कि हमें संधि करनी लेनी चाहिए थी, वार्ता सफल कर देनी चाहिए थी और पाकिस्तान की शर्तों पर कर देनी चाहिए थी। मुझे मालूम है, एक भी आदमी नहीं होगा। â€¦(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : हम देश के सम्मान और स्वाभिमान की कीमत पर हम एक इंच भी जमीन नहीं देना चाहते हैं। â€¦(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : मैं समझता हूं कि वार्ता का कोई आधार नहीं बना और वार्ता विफल हुई, यह सबसे बड़ी सफलता है। जिन्होंने पाकिस्तान को एक-तिहाई काश्मीर दे दिया, पीओके के बारे में पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बताया है। यह बात उन्होंने लीडर्स की मीटिंग में बताई थी और वे माधवराव सिंधिया जी को न बतायें, तो उसमे मेरा कसूर नहीं है। मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान अधिग्रहीत क्षेत्र के बारे में खुले तौर पर बताया गया है और उनको कहा गया है कि अगर काश्मीर कोर इशू है, तो काश्मीर के कोर इशू की कोर में जाना पड़ेगा । कबाइलियों ने हमला किया था । मैं उस दिन काश्मीर में था और मुझे मालूम है, हिन्दुस्तान के लोगों ने, हिन्दुस्तान की सेना ने, किस तरीके से काश्मीर को बचाया था। यह तो और बात थी, 1971 में भी और उस समय भी पाकिस्तान झुक जाता, चांद और सितारे झुक जाते, परन्तु इन्होंने उस समय कर दिया। उसको रोक दिया। वहां पर युद्धबन्दी कर दी और युद्धबन्दी करके पाकिस्तान को दे दिया। मैं मुलायसिंह सिंह जी से सौ फीदसी सहमत हूं।

18.00 hrs.

हमारे सैनिक जिस काम के लिए अपना खून बहाते रहे, वार्ता की मेज पर उसे धो दिया गया। हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने इस बात को नहीं होने दिया, एक बार उस परम्परा को तोड़ दिया। यह परम्परा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की चल रही है। यह कहा जाता है कि यही हमारी संस्कृति है। किसी ने तो उसे तोड़ा है, किसी ने तो कहा है कि हम वार्ता करेंगे परन्तु वार्ता के आगे किसी बात में नहीं झुकेंगे। आज सदन में सब बताएं, माधवराव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो को वहां नहीं जाना चाहिए, जब तक पाकिस्तान यह न माने,...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने नहीं कहा है।...(व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : माधवराव जी ने यह बात कही, उन्हें बता देना चाहिए। ...(व्यवधान) स्ट्रक्चर्ड डिबेट हो, पहले एजेंडा तय हो।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आपको स्पट कर दूं, मैंने यह कहा- when you go to Pakistan, please do not go without a structured agenda, without being properly prepared. That is what I said.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : That is exactly what I am saying. यही बात मुलायम सिंह जी ने कही है। मैं कह रहा था कि सदन इस बात पर अपनी भावना व्यक्त करे कि अगर पाकिस्तान कश्मीर की समस्या के बिना और बातचीत करने को तैयार न हो, स्ट्रक्चर्ड डिबेट के लिए तैयार न हो, शिमला समझौते और लाहौर समझौते को न माने तथा आधार न बनाए, क्रॉस बार्डर टेरेरिज़्म को खत्म करने की बात न करे और कहे कि आप वहां आओ, बात करो तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। let this House express its opinion. मुझे बड़ा दुख होता है जब कुछ नेता बाहर कहते हैं कि जरूर जाना चाहिए, खुली बात करनी चाहिए। सीपीएम ने यह स्टैंड दिया है कि डायलॉग जरूर होने चाहिए, उसी में से रास्ता निकलेगा। यही प्रणव मुखर्जी जी कह रहे हैं और यही बाकी नेता कहते हैं। वहां एक बात करते हैं और यहां आकर दूसरी बात शुरु कर देते हैं। कंफ्यूज़न इसी बात पर है। यहां अपनी पार्टी के हितों को, देश के हितों को ऊपर देखते हैं। इसलिए कम से कम आज जो शिखर वार्ता हुई, उसकी सबसे बड़ी सफलता मैं यह समझता हूं कि पहली बार पाकिस्तान को पता लग गया कि हिन्दुस्तान से बातचीत करते हुए इस तरह की चीजों पर, अपनी शर्तों पर भारत को झुकाया नहीं जा सकता। इसके लिए सारा देश प्रधानमंत्री जी को बधाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

18.04 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, July 25, 2001/Sravana 3, 1923 (Saka)